

लेख, कविताएं एवं विज्ञापन प्रकाशनार्थ आदि के लिए स्थानीय संपादक इपतेखार उददीन खान से संपर्क करें
मो. 9977442619
9425442435

राष्ट्रीय जनवक्ता

राजगढ़ जिले का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र

लेख, कविताएं एवं विज्ञापन प्रकाशनार्थ आदि के लिए उप संपादक कमरुउद्दीन खान से संपर्क करें
मो. 9340636911
9425442435
आनंद एक्सीलेंस कॉलेज के सामने, वार्ड नं. 2, ब्यावरा (राजगढ़) मप्र

वर्ष-22 अंक- 320

(सांध्य दैनिक)

राजगढ़, रविवार 31 मई 2026

पृष्ठ-8

मूल्य-1 रूपया

सांक्षिप्त समाचार

मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, नोटिस पर भड़के अभिषेक बनर्जी

कोलकाता आवास पर सीआईडी के नोटिस को लेकर कोहराम

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के निशाने पर आने के बाद टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि उन्हें जो करना है करने दो। वे जो चाहें कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, पहले सिर्फ ईडी और सीबीआई थीं, और अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी उनके साथ है। साथ ही कोलकाता नगर निगम भी। पहले 2-3 जांच एजेंसियां थीं, और अब 5 हो गई हैं। उन्हें लगता है कि वे मेरे पीछे 5-6 एजेंसियां लगा देंगे और मुझे डरा-धमकाकर झुका देंगे। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। बनर्जी ने कहा



कि तुम चाहे मेरा गला काट दो या जो चाहो कर लो, मुझे झुकाने के लिए तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा और 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया है वह मामला विधानसभा में विधायकों के फर्जी दस्तखत से जुड़ा है।

बढ़ेंगे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें

कोलकाता नगर निगम का संपत्ति नोटिस दिया था। यह नोटिस अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों और उनके आवासों में कथित अवैध निर्माण को लेकर है। सीआईडी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की टीम ने उनके कालीघाट स्थित आवास पर कानूनी नोटिस चरपा किया है।

दिल्ली के लिए मंत्री पद छोड़ने को तैयार छगन भुजबल!

● किसे राज्यसभा में भेजेंगी सुनेत्रा पवार, एनसीपी नेता का प्लान

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पास राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। इनमें से 18 सीटें भरी हुई हैं। सिर्फ एक सीट खाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हुई है। इसी सीट से राज्य सभा जाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल पुरा जोर लगा रहे हैं। अभी तक इस सीट से राज्यसभा कौन जाएगा। सुनेत्रा



पवार की एनसीपी ने तय नहीं किया है। राजनीति हलकों में चर्चा है कि इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सक्रिय रूप से लॉबी कर रहे हैं। भले ही भुजबल ने सार्वजनिक रूप से राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन पर्दे के पीछे इस सीट के लिए उनकी कोशिश तेज हो चुकी है। चर्चा है कि वे अपने भतीजे समीर भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए भी जोर लगा रहे हैं। हालांकि अभी उनका दो साल बाकी है।

जल संरक्षण हमारा सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य

● सीएम डॉ. यादव बोले-जल संरक्षण में अग्रणी राज्य बना अपना प्रदेश ● मुख्यमंत्री ने कहा-प्रदेश भर में संवर रहे हैं पुराने पारंपरिक जल स्रोत

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है और हमारी पारंपरिक जल संरचनाओं को संरक्षित और संवर्धित करना हमारा परम सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य है। इसी पावन उद्देश्य के साथ राज्य में शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान आज केवल एक शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से एक पवित्र जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और पुनर्जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जल सहेजने के इस पुनीत कार्य में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।



● देश के लिए मिसाल बनेगा एमपी का जल प्रबंधन मॉडल- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश की जागरूक जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समर्पित प्रशासनिक अमले को देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का यह सशक्त जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए एक नई और अनुकरणीय दिशा तय करेगा। आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मध्यप्रदेश इस दिशा में निरंतर नवाचार करता रहेगा।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई जल क्रांति

ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड 57,794 खेत तालाब और 91,838 डग वेल रिचार्ज (कुआं पुनर्भरण) संरचनाओं का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और नए जल स्रोतों को सहेजने के उद्देश्य से 29,906 जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाओं तथा 126 भव्य अमृत सरोवरों का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,152 विशेष सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पुरानी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए 2,721 मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत सामाजिक, पर्यावरणीय और शैक्षणिक स्तर पर भी विशेष प्रयास किए गए हैं। वाटरशेड प्रबंधन के तहत 4,822 कार्यों को पूर्ण किया गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर में व्यापक सुधार होगा। वहीं, स्कूलों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से 5,275 पानी की टंकियों की सफाई का कार्य संपन्न कराया गया है। इसके अलावा, जल संसद जल बंधन 2.0 पहल के तहत 21.23 लाख से अधिक कार्यों का सफल पंजीकरण किया गया है, जिसमें समय पर कार्य पूर्ण करने की उत्कृष्ट दर 91.3 फीसदी दर्ज की गई है।

कच्चा तेल, मॉनसून, महंगाई, रुपए में गिरावट...

● इकॉनमी के हालात पर आ गया सरकार का रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपना मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जारी किया। इसमें कहा कि मई में भारत की व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) स्थिति सतर्क लेकिन मजबूत बनी हुई है। मजबूत सेवा निर्यात, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर श्रम बाजार ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतें, रुपये में कमजोरी, उत्पादन लागत में बढ़ती दबाव और सामान्य से कम मॉनसून की संभावना ऐसे कारक हैं, जिनके चलते नीति निर्माताओं को लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया, वित्त वर्ष 2026-27 में विकास की रफ्तार बनाए रखने और महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए मौद्रिक, राजकोषीय और संरचनात्मक नीतियों में लचीलापन और सक्रियता जरूरी होगी।



महंगाई का दबाव रुपए में गिरावट

ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि के कारण महंगाई का दबाव फिर बढ़ा है, और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन (कम विकास और ऊंची महंगाई) की चिंताएं दोबारा उभरने लगी हैं। समीक्षा में कहा गया है कि यदि खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान बना रहता है, तो इससे वैश्विक आर्थिक विकास और कमजोर हो सकता है तथा कई देशों की आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत के लिए भी इन बाहरी दबावों का असर अब धीरे-धीरे घरेलू अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट में कहा गया, अप्रैल 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति बनाए रखी। ई-वैबिल जनरेशन, पीएमआइ सूचकांक और बिजली खपत वृद्धि के दायरे में बने रहे। हालांकि, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक और इंधन खपत में नरमी यह संकेत देती है कि वैश्विक चुनौतियों का असर घरेलू अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर पड़ने लगा है। अप्रैल 2026 के महंगाई आंकड़ों का जिक्र करते हुए समीक्षा में कहा गया कि उपभोक्ता महंगाई और थोक महंगाई के बीच अंतर बढ़ा है।

गेहूँ-चावल का स्टॉक

इन अल्पकालिक जोखिमों के बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस साल मॉनसून को दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का लगभग 92 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। समीक्षा में कहा गया कि देश के पास 817.53 लाख टन चावल और गेहूँ का बफर स्टॉक मौजूद है तथा जलाशयों में भी पर्याप्त जल भंडारण है, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा को सहारा मिलेगा। हालांकि, यदि वर्षा में बड़ी कमी रहती है और मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, ग्रामीण मांग कमजोर हो सकती है और समग्र आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। अप्रैल 2026 में औद्योगिक गतिविधियों में कुछ नरमी देखी गई।

एमपी में अब 16 जून से खुलेंगे सरकारी स्कूल

● स्कूल चलें हम अभियान भी चलेगा, गर्मी को देखते हुए शिक्षकों का अवकाश भी बढ़ाया

भोपाल। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होगी। इसके साथ ही इसी दिन से स्कूल चलें हम अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए शिक्षकों के लिए 7 दिन का अवकाश बढ़ाया है। यानि अब शिक्षकों को 1 जून की बजाय 7 जून से विद्यालय में उपस्थित देनी होगी। प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही



थी। इसके बाद अब सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल चलें हम अभियान के दौरान सबसे अधिक फोकस ड्रॉप आउट बच्चों को फिर विद्यालय से जोड़ने और शाला प्रारंभ उत्सव मनाए जाने का काम होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित कराएं। इसका उद्देश्य सौ फीसदी प्रवेश सुनिश्चित करना, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना अनिवार्य है।

होर्मुज छोड़ने को तैयार नहीं है ईरान

● अमेरिका के साथ डील पर तेहरान की दो टूक ● कहा-अमेरिका से अभी तक कोई समझौता नहीं

तेहरान (एजेंसी)। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर अड़ा हुआ है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ अभी तक किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बाकेई ने सरकारी टीवी चैनल आईआरआईटीवी के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिका के साथ समझौते पर कहा कि दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ



दावे 'विश्वगुरु' के, मगर हर परीक्षा में 'फेल': राहुल गांधी

● नीट को लेकर कांग्रेस नेता का पीएम मोदी पर बड़ा हमला ● कहा-वह देश में एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं करवा सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैटल पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई,एसएससी और आज सीयूईटी, चार परीक्षाएं और एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते-मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वहीं पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। सरकार के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैटल एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के



ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यह तीखी प्रतिक्रिया केंद्र

सरकार द्वारा आगामी नीट पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद आई है। साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैटल पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। नीट पेपर लीक और सीबीएसई की अब राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के तंज पर नसीहत दे डाली। बीजेपी ने नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपरिपक्व नेता की तरह बात करते हैं। विपक्ष के नेता ने जिम्मेदारी दिखाने के बजाय सनसनी फैलाने का रास्ता चुना है।

राहुल सनसनीखेज आरोप लगाने के बजाय तथ्य पेश करें- गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के इस तरह के बेटुके बयान उनकी अपरिपक्वता और गैर-जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, जिसके साथ वे भारत के युवाओं से जुड़े हर संवेदनशील मुद्दे को संभालते हैं। विपक्ष के नेता से अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य प्रस्तुत करें, न कि केवल राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बेटुके और सनसनीखेज आरोप लगाएं। ऐसे बयान लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते; वे जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और लाखों उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं को तुच्छ।

संभावित समझौते के लिए अपनी शर्तें सार्वजनिक की हैं। बाकेई ने दोहराया कि बातचीत में ईरान का मौजूदा ध्यान युद्ध को खत्म करने पर है। उन्होंने कहा, इस चरण पर हम ईरान के यूरेनियम संवर्धन या समृद्ध यूरेनियम से जुड़े मुद्दों के विवरण पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के संभावित रूप से फिर से खुलने के बारे में बात करते हुए बाकेई ने कहा कि इस स्ट्रेट का भविष्य एक प्रबंधन सिर्फ ईरान और ओमान से संबंधित है। इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मांगें बताते हुए कहा, ईरान को इस बात पर सहमत होना होगा कि उनके पास कभी भी कोई परमाणु हथियार या बम नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोला जाना चाहिए और दोनों दिशाओं में जहाजों की आवाजाही पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं होना चाहिए।

विकास कार्यों का जायजा लेने कुरवाई तहसील पहुंचे अंशुल गुप्ता, ग्रामीणों से किया संवाद

विदिशा, निप्र। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज शुरुवार को कुरवाई तहसील के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करमेड़ी, माला, महलुआ, भौरासा और कांकर ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया तथा योजनाओं के लाभ मिलने में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सबसे पहले ग्राम करमेड़ी पहुंचकर नवनिर्मित सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया।

इसके बाद उन्होंने सामुदायिक भवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदनों को मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। इसके बाद कलेक्टर श्री गुप्ता ग्राम माला पहुंचे, जहां उन्होंने नव निर्मित पंचायत भवन का अवलोकन किया। साथ ही ग्राम में संचालित नल-जल योजना की प्रगति और एक बगिया मां के नाम अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजनाओं के बेहतर संचालन और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महलुआ चौराहा में कलेक्टर ने पुस्तकालय एवं उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई तथा ग्रामीणों को बेहतर



सुविधाएं देने पर विशेष जोर दिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया।

भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ग्राम भौरासा भी पहुंचे, जहां उन्होंने उचित मूल्य दुकान, पंचायत भवन एवं नवनिर्मित आयुष्म औषधालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से मिलना सुनिश्चित

किया जाए। कलेक्टर ने राशन वितरण व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण एवं पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ग्राम कांकर में एक बगिया मां के नाम के तहत किए गए कार्यों का अवलोकन किया। यहां उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद किया और समूह के माध्यम से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के अनुभव जाने। महिलाओं ने स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। कलेक्टर के इस दौर से ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया तथा अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

खरीफ 2026 हेतु खाद उपलब्धता एवं मंडारण की समीक्षा बैठक

नर्मदापुरम, निप्र। शुरुवार को कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में नर्मदापुरम जिले में आगामी खरीफ मौसम 2026 हेतु खाद की उपलब्धता एवं भंडारण संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीता कौरी, उपसंचालक कृषि श्री रविकांत सिंह, उपायुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा, जिला विपणन अधिकारी श्री अनिल जैन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के प्रबंधक तथा जिला प्रबंधक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम श्री सोनू सैजकर उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जिले में खाद की उपलब्धता एवं भंडारण की विस्तृत समीक्षा की गई। उपसंचालक कृषि द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में कुल 48 हजार 219 मे.टन उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें यूरिया 21 हजार 568 मे.टन, टी.एस.पी. 4 हजार 50 मे.टन, एन.पी.के. 7 हजार 540 मे.टन, एस.एस.पी. 14 हजार 537 मे.टन तथा एम.ओ.पी. 524 मे.टन शामिल है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले के 6 डबल लॉक केंद्रों पर 10 हजार मे.टन यूरिया एवं 7 हजार मे.टन फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है। वहीं उपायुक्त सहकारिता द्वारा जानकारी दी गई कि जिले की कुल 99 समितियों में से 94 समितियों में 7 हजार 800 मे.टन यूरिया का भंडारण किया गया है तथा 27 समितियों में 142 मे.टन फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने नवाचार अपनाएं: कलेक्टर

► पंचायतों की पणियों का निरीक्षण, स्वच्छता और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर दिए निर्देश

विदिशा, निप्र। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायतों के भ्रमण के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने पंचायतों में संचालित विभिन्न पणियों एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से संवाद करते हुए ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नवीन और व्यवहारिक विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि ग्राम पंचायतें केवल शासकीय अनुदानों पर निर्भर न रहें, बल्कि

स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से अपनी आय के नए स्रोत विकसित करें। उन्होंने पंचायतों में स्थित वेयरहाउस, बहुउपयोगी भवनों एवं अन्य परिसरों का व्यवस्थित सर्वे कर उन पर संपत्ति कर निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों की आय बढ़ाने से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि आय का माध्यम भी बन सकती है। पंचायतें यदि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करें तो उससे आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

तालाब की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, ग्राम पंचायत को सौंपा गया कब्जा

विदिशा, निप्र। विदिशा तहसील के ग्राम किरमची में आज राजस्व अमल द्वारा तालाब की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार की मौजूदगी में राजस्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संपादित की गई। कार्रवाई के दौरान तालाब की भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाया गया, ताकि जल स्रोत को संरक्षित किया जा सके तथा ग्रामीणों को भविष्य में जल संरक्षण का लाभ मिल सके। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने के उपरंत संबंधित भूमि का कब्जा विधिवत ग्राम पंचायत के संपर्क एवं सचिव को सौंप दिया गया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए तालाब क्षेत्र को सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि शासकीय भूमि एवं जल स्रोतों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

रोजगार की पढ़ाई चले आईटीआई

विदिशा, निप्र। जिले की समस्त शासकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विदिशा जिला अंतर्गत 7 शासकीय आईटीआई में विभिन्न ट्रेड जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, ट्रेक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सुगुण टेक्नोलॉजी, ड्रॉन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), एवं वर्तमान परिप्रेष्य के अनुरूप सोलर टेक्नीशियन ट्रेड प्रारंभ की गई है। इच्छुक आवेदक 26 मई 2026 से विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर जाकर 'प्रवेश 2026' में जाकर स्वयं के मोबाइल, कंप्यूटर, अथवा एमपीऑनलाइन पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। आवेदकों के सहयोग हेतु समस्त शासकीय आईटीआई में हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है। आवेदक किसी भी समस्या के समाधान, अधिक जानकारी हेतु अथवा पंजीयन हेतु निकटतम शासकीय आईटीआई में जाकर पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु आवेदक संस्था के प्रवेश प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। जिले की समस्त सभी सातों शासकीय आईटीआई में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विकास खंडवार प्रवेश प्रभारियों से उनके मो. नं. पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना के हितग्राही बीमा नवीनीकरण अवश्य कराएं

विदिशा, निप्र। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाय और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेबीवाय के सभी सम्मानित हितग्राहियों से जिला अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह अपने बीमा पॉलिसियों को सक्रिय रखने के लिए अपने बैंक खातों में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखें। इस हेतु दोनों बीमा योजनाओं का वार्षिक प्रीमियम राशि पीएमएसबीवाय हेतु 20 रुपये एवं पीएमजेबीवाय हेतु 436 रुपये जिसमें खाते में कुल राशि रु. 456 शेष जमा रखना अनिवार्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएमएसबीवाय और पीएमजेबीवाय पॉलिसियों को वार्षिक नवीनीकरण 01 मई से 31 मई 2025 के बीच किया जाता है। यदि हितग्राहियों खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण स्वतः ही फेल हो सकता है, और आपको इन महत्वपूर्ण बीमा योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।



बीपीएल सूची के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश

विदिशा, निप्र। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज कुरवाई तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के भ्रमण के दौरान राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामवार बीपीएल सूची का सत्यापन अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके, इसके लिए बीपीएल सूची का अद्यतन एवं वास्तविक स्थिति के अनुरूप सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम में घर-घर जाकर बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों की स्थिति का परीक्षण किया जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम चिन्हित कर

आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही पात्र लेकिन सूची से वंचित परिवारों की जानकारी भी संकलित की जाए, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य पूरी पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ग्राम स्तर पर राजस्व अमला, पंचायत सचिव एवं संबंधित विभागों के कर्मचारियों के समन्वय से यह अभियान संचालित होगा। कलेक्टर ने इस प्रकार का अभियान जिले की अन्य तहसीलों में भी समानांतर रूप से संचालित करने के निर्देश सभी एसडीएमों को दिए हैं।

विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



नर्मदापुरम, निप्र। माहवारी स्वच्छता दिवस के अन्तर्गत इटारसी नगर के वाई क्रमांक 23 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 47 में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों एवं महिलाओं को माहवारी स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक करना रहा।

यह कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी की अधीक्षक कमलेशा कुमारे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अस्पताल से उमंग काउंसलर जिलोक मनवारे ने किशोरियों को माहवारी स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित आहार लेने एवं स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने

कहा कि माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे जुड़े धर्म एवं संकोच को दूर करना आवश्यक है। स्वच्छता अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। सीडीपीओ प्रभारी दीप्ति शुक्ला एवं सेक्टर सुपरवाइजर राखी मौर्य ने किशोरियों को नियमित रूप से स्वच्छ सेनेटरी पैड के उपयोग तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने एवं अन्य बालिकाओं को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित किशोरियों को सेनेटरी पैड वितरित किए गए। इसके बाद वार्ड में माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से माहवारी स्वच्छता से जुड़े संदेश आमजन तक पहुंचाए गए। इस अवसर पर सुपरवाइजर अर्चना बस्तवार, मोना गाठले एवं रेखा चौरै द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित कराए गए। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोनिका, स्थानीय महिलाओं एवं किशोरियों बालिकाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

सोलर टेक्नीशियन प्रशिक्षार्थियों की ऑन जाँव ट्रेनिंग सम्पन्न

विदिशा, निप्र। शासकीय आईटीआई विदिशा में संचालित सोलर टेक्नीशियन व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों हेतु ऑन जाँव ट्रेनिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सोलर पैनल स्थापना, रखरखाव, वायरिंग, ऊर्जा संरक्षण एवं आधुनिक सौर तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। योजना के माध्यम से घरों में सोलर ऊर्जा के उपयोग, बिजली बचत तथा स्वरोजगार के अवसरों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों को सोलर उद्यमिता विकास का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें स्वयं का सोलर व्यवसाय प्रारंभ करने, ग्राहकों से संपर्क, इंस्टॉलेशन कार्य, सर्विसिंग एवं सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के विषय शामिल रहे।

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कुरवाई क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर शासकीय योजनाओं का लिया जायजा

एक बगिया मां के नाम से लाभान्वित हितग्राही के कार्यों का जायजा

विदिशा, निप्र। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज कुरवाई क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति का जायजा पहुंच कर लिया है। इस दौरान उन्होंने लाभान्वित हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके व परिवार के सदस्यों के जीवन में आए बदलाव को जाना है। ग्राम पंचायत कांकर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत विकास कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांव के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम कांकर में मनरेगा योजना के तहत एक बगिया मां के नाम योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती मथुराबाई पति श्री



कुंअर सिंह द्वारा अभियान अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। इन कार्य के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार एवं सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की पहलें गांवों में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही हैं। योजना संबंधी जानकारी के अनुसार कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत कांकर है तथा कार्य का निष्पादन निर्धारित स्वीकृति एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर लगाए गए सूचना बोर्ड में कार्य की लागत, मजदूरी दर, कार्य अवधि एवं श्रमिकों की संख्या का उल्लेख किया गया है,

जिससे कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। इससे ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित इस प्रकार के कार्यों से ग्रामीणों में उत्साह का वातावरण है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से गांव में विकास कार्यों को गति मिली है और लोगों को नियमित रोजगार उपलब्ध हो रहा है। प्रशासन द्वारा भी मनरेगा कार्यों को सतत मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराए जा सकें। ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल ग्राम कांकर के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन रही है।

नर्मदापुरम में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के तहत जागरूकता रैली और नुकड़ नाटक का आयोजन



नर्मदापुरम, निप्र। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम में तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। तंबाकू उत्पादों एवं ई-सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाने के लिए नुकड़ नाटक का मंचन किया गया। साथ ही चिकित्सालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य

कर्मियों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चिकित्सालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तंबाकू मुक्त जीवनशैली अपनाने और अपने कार्यस्थल को पूर्णतः तंबाकू मुक्त रखने की शपथ ली। अस्पताल परिसर में जगह-जगह पोस्टर और बैनर लगाकर मरीजों व स्टाफ को तंबाकू से होने वाले कैंसर, हृदय रोग व

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरसिंह गहलोत के निर्देशन और सिविल सर्जन डॉ. सुनीता कर्कर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आर.एम.ओ. डॉ. गजेंद्र यादव, दंत चिकित्सक एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. राजनी कुंआवाह, डॉ. अखिलेश सिंघल, डॉ. मिलन सोनी, डॉ. दिव्या पटेल, डॉ. इति वर्मा, डॉ. श्वेता कौशिक, तंबाकू निवारण केंद्र परामर्शदाता हेमलता पटेल, राजकुमार यादव सहित चिकित्सालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

फेफड़ों की बीमारियों के बारे में सचेत किया गया। जिला चिकित्सालय स्थित तंबाकू निवारण केंद्र में तंबाकू की लत छोड़ने के लिए निःशुल्क परामर्श और निकोटिन रिप्लेसमेंट टैबलेट उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में 25 मई से 31 मई 2026 तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले भर में तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।



यात्री बसों एवं डंपरों पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

8 वाहनों से वसूला गया 95 हजार 500 रुपये शमन शुल्क

विदिशा, निप्र। परिवहन आयुक्त द्वारा यात्री बसों में सुरक्षा मानकों की सख्त जांच सुनिश्चित करने हेतु जारी निर्देशों के पालन में जिला परिवहन विभाग विदिशा द्वारा गुरुवार को अशोकनगर रोड पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा द्वारा किया गया। जांच अभियान के दौरान यात्री बसों एवं डंपर वाहनों की गहन जांच की गई। परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, सुरक्षा उपकरणों

सहित अन्य आवश्यक मानकों का परीक्षण किया। जांच में कई वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। कार्रवाई के दौरान कुल 08 वाहन नियम विरुद्ध संचालित होते पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित वाहन चालकों एवं संचालकों से कुल 95 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरिजेश वर्मा ने बताया कि यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

बढ़ती गर्मी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पीते रहें : सीएम डॉ. यादव

इन्दौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान और अधिक गर्मी से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने और बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान और अधिक गर्मी देखते हुए सभी प्रदेशवासी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त पानी पीएं, बच्चों को हाइड्रेटेड रखें और बाहर निकलते समय पानी की बोतल अवश्य साथ रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवाभावी नागरिकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था करना मानवता की सच्ची सेवा है। हम सभी को इस दिशा में आगे आना चाहिए।

सावरकर जयंती पर धार में संगोष्ठी, माय भारत पोर्टल से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें युवा

धार। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'मेरा युवा भारत' धार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी और अद्वितीय विचारक विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) की जयंती के अवसर पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खेल और युवा कल्याण विभाग के ' आरोह 2026 ' समर कैंप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हाई कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता श्री अंशुल राजपुरोहित का स्वागत ब्लॉक समन्वयक अनिरुद्ध चावड़ा ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री अंशुल राजपुरोहित ने कहा कि ' वीर सावरकर का पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था। सावरकर जी ने न केवल देश की आजादी के लिए अंडमान की सेलुलर जेल में 'काला पानी' की अमानवीय यातनाएं सहई, बल्कि उन्होंने समाज में फैले छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी पूरजोर आवाज उठाई। उनका राष्ट्रवाद और सामाजिक चिंतन आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक है।' कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माय भारत की जिला युवा अधिकारी श्रीमती दीप्ती राजावत ने अपने संबोधन में युवाओं को विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने 'मेरा युवा भारत' द्वारा वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही, उन्होंने उपस्थित सभी युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'माय भारत पोर्टल' पर अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर शालिनी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिविर के प्रतिभागी और स्थानीय युवा उपस्थित रहे।

धार जिला कार्यालयों के लिए निजी वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित,

धार। कलेक्टर कार्यालय जिला धार द्वारा शासकीय कार्यों के सुचारु संपादन हेतु निजी वाहन किराये पर लेने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह निविदाएं आगामी 8 जून 2026 को दोपहर 2:00 बजे तक स्वीकार की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि इच्छुक निविदाकर्ता निर्धारित प्रारूप में तकनीकी और वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफों में भरकर जमा कर सकते हैं। तकनीकी निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में 20,000 रुपये की एफडी कलेक्टर धार के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता को शासकीय कार्यालयों में शासकीय कार्य के लिए वाहन व्यवस्था करने का पूर्ण अनुभव होना अनिवार्य है। फर्म का विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 10 लाख रुपयों या उससे अधिक होना चाहिए, जिसे सीए द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। साथ ही विगत 3 वर्षों का आईटीआर संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक के पास फर्म स्थापना पंजीयन, जीएसटी पंजीयन और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। निविदा के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन व्यावसायिक परिवहन यान (पीली टैक्सी परमिट) के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में जीवित पंजीयन के साथ दर्ज होने चाहिए।

नकली बायो डीजल बेचने वाले मे. इंदौर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मेथवाडा देपालपुर बायो डीजल पंप पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई



इन्दौर। इंदौर जिले के देपालपुर मेथवाडा स्थित मे. इंदौर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बायो डीजल पंप भागीदार सुनीता पति सुभाष केसवाल एवं सुभाष पति रामचंद्र केसवाल निवासी 1525 द्वारकापुरी इंदौर द्वारा अवैध रूप से नकली बायो डीजल की बिक्री करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने पंप को मौके पर सील कर दिया है। मे. इंदौर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बायो डीजल पंप पर प्रारंभिक जाँच के नकली बायो डीजल होना पाया गया है। जांच की कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री शिव सुंदर व्यास देपालपुर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री अजय अस्थाना द्वारा की गई।

बताया गया कि मे. इंदौर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बायो डीजल पंप की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा जांच की गई। प्रारंभिक जांच में नकली

बायो डीजल पाए जाने पर पंप को सील किया गया है। इसके साथ ही पंप संचालक द्वारा राज्य सरकार के अधिकृत लाइसेंस प्राप्त छह कंपनी के सप्लायर से सप्लाइ नहीं लेकर अनाधिकृत फर्म से सप्लाइ लेना पाया गया। बताया गया कि पंप संचालक इन्फो100 मानक का ही बायो डीजल विक्रय कर सकते हैं, बायोडीजल के मानक की डेंसिटी 900 से ऊपर होती है परंतु मौके पर डेंसिटी 860 पाई गई।

मौके से कुल 6000 लीटर नकली बायो डीजल जप्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 20 हजार रुपये से अधिक है। नकली बायोडीजल के सैम्पल लेकर पंप में बिक्री बंद करवाते हुए पंप, डिस्ट्रिब्यूटरी यूनिट और भूमिगत टैंक को सील कर दिया गया है। बताया गया कि सैम्पल अधिकृत लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। नमूना रिपोर्ट आने के बाद में आगामी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

9 से 13 जून तक होगा अंतरराष्ट्रीय BRICS कृषि सम्मेलन

तैयारियों का कलेक्टर-पुलिस कमिश्नर और अन्य सभी अधिकारियों ने बसों में बैठकर लिया जायजा

इन्दौर। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि विषय पर अंतरराष्ट्रीय महत्व का BRICS सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में BRICS देशों के मंत्रिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आज पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह और कलेक्टर श्री शिवम वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रम स्थलों, बैठक स्थलों तथा अतिथियों के आवागमन मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एयरपोर्ट से लेकर अतिथियों के ठहरने के स्थानों तथा आयोजन स्थलों तक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए कि मेहमानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मालवा की सांस्कृतिक गरिमा और पारंपरिक आतिथ्य के अनुरूप उनका स्वागत-सत्कार सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एयरपोर्ट से मेरियट होटल और शैरेटन ग्रेड पैलेस तक के मार्ग का बसों के माध्यम से भ्रमण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री श्रितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री अर्थ जैन, एमपीआईडीसी के कार्यकारी अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रोशन राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बताया कि अधिकारियों



की ब्रीफिंग, दायित्व निर्धारण और समन्वय संबंधी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर बैठक स्थलों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के ठहरने वाले स्थानों तक पूरे रूट प्लान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इंदौर और भारत के लिए गौरव का अवसर है। इसलिए प्रशासन पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है ताकि आयोजन में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इंदौर पूर्व की तरह इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन का भी सफलतापूर्वक संचालन करेगा।

कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश में कृषि वर्ष मनाया जा रहा है। इसी के तहत सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। ढक्कन वाला कुआँ स्थित हाट बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर कृषि आधारित प्रदर्शियाँ एवं स्टॉल लगाए जाएँगे, जहाँ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को प्रदेश के कृषि विकास मॉडल और नवाचारों की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वाहन पूलिंग और ईंधन बचत के संदेश को भी व्यवहार में उतारा। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने बसों के माध्यम से संयुक्त

रूप से भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ समन्वित निरीक्षण भी संभव हुआ और भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।

इंदौर का यह सम्मेलन मध्यप्रदेश सहित भारत और पूरी दुनिया के कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे मुद्दों पर नई दिशा देगा, बल्कि इंदौर को अंतरराष्ट्रीय कृषि संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि इस बार BRICS सम्मेलन 2026 भारत में हो रहा है और कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के लिए मध्यप्रदेश के इंदौर का चयन किया गया है। आगामी 9 से 11 जून 2026 तक इंदौर में BRICS कृषि कार्य समूह (AWG) की बैठक होगी, जबकि 12 और 13 जून 2026 को सदस्य देशों के कृषि मंत्री यहाँ एकत्रित होकर कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

इंदौर में होने वाली बैठक में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, कृषि व्यापार को आसान बनाने, किसान कल्याण, आपूर्ति शृंखला, अनुसंधान, ज्ञान साझेदारी, डिजिटल कृषि, प्रिंसिपल फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लॉगिंग, रोबोटिक्स और नवाचार जैसे विषयों पर गंभीर मंथन होगा।

विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर जनजागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित

इन्दौर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी के मार्गदर्शन एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिले में व्यापक जनजागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवसर पर जीवन ज्योति हॉस्टल राऊ, सिविल चिकित्सालय महू सहित स्वास्थ्य विभाग की समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित मोबाइल हेल्थ टीमें द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों एवं छात्रावासों में किशोरियों एवं महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा स्वास्थ्य परीक्षण किए गए।

कार्यक्रम में बताया गया कि आज भी समाज के अनेक हिस्सों में माहवारी को



लेकर भ्रांतियां एवं संकोच की भावना विद्यमान है। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस का उद्देश्य इन मिथकों को दूर कर नागरिकों, विशेष रूप से किशोरियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ माहवारी व्यवहार को बढ़ावा देना है। माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने पर संक्रमण एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सैनिटरी पैड, स्वच्छ कपड़े एवं साफ पानी के उपयोग के प्रति

जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि अनेक किशोरियां माहवारी के दौरान आवश्यक सुविधाओं के अभाव में विद्यालय नहीं जा पाती हैं। यह दिवस उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माहवारी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जिसे लेकर किसी प्रकार की शर्म या संकोच की आवश्यकता नहीं है।

28 मई को ही वयों मनाया जाता है विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस :

विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य माहवारी चक्र औसतन 28 दिनों का होता है तथा माहवारी की अवधि लगभग 5 दिनों की मानी जाती है। इसी आधार पर 28/5 अर्थात् 28 मई की तिथि को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के रूप में चुना गया है।

विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को विश्वभर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन एवं किशोरियों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मिथकों एवं भ्रांतियों को दूर करना तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ माहवारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में किशोरियों एवं महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन भी वितरित किए गए।

मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इन्दौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूँ उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूँ उत्पादन किसानों को 2585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस का लाभ दिया है। किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ का भुगतान किया। अब तक किसानों को गेहूँ उपार्जन की 24 हजार करोड़ राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में आज वीडियो संदेश के माध्यम से ये जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूँ खरीदने के लिए किसानों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूँ की पैदावार बढ़ी है। देश में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाले राज्यों में पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश सर्वाधिक लंबे समय तक गेहूँ खरीद की व्यवस्था लागू करने वाला एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों से पहले गेहूँ खरीदा गया। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की गई। छोटे किसानों से अब तक लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया है। इसके बाद बड़े किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिला। अब तक लगभग पौने 1.4 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन कर लिया गया है। सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसान भाई-बहनों का गेहूँ गोदाम तक पहुंच चुका है।

भारत को अक्षय ऊर्जा की वैश्विक महाशक्ति बना रही पीएम सूर्य घर योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इन्दौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के साथ सशक्त भारत की दिशा में केन्द्र सरकार के बढ़ते कदमों का ही सुरणिगम है कि आज देश के 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित हो गए हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 1 लाख 29 हजार 971 घर शामिल हैं। ये सभी घर-परिवार अब बिजली बिल की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त होकर स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा से रौशन हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में स्थापित इन सोलर संयंत्रों से 456 मेगावॉट से अधिक स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के नेशनल पोर्टल के अनुसार इस योजना से अब तक प्रदेश के 1 लाख 34 हजार 436 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के पीएम सूर्य घर योजना हितग्राहियों को अब तक 901.92 करोड़ रुपये की अनुदान (सब्सिडी) राशि रिलीज की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में 6 लाख घरों को 'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के तहत सौर ऊर्जा से रौशन करने का लक्ष्य लिया गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तेजी से काम जारी है।

कलेक्टर श्री मीना ने स्वास्थ्य संबंधी विभागों की बैठक ली

गर्भवती महिलाओं के पंजीयन शुरुआती समय में ही शत प्रतिशत महिलाओं का पंजीयन कराए- कलेक्टर

धार। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सर्विलेंस समिति, मेडिकल कॉलेज, पोषण समिति, महिला बाल विकास विभाग एवं जिला आयुष मिशन सोसायटी संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, एनीमिया प्रबंधन, संस्थागत प्रसव तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं ऑडिट पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन पर विशेष जोर देते हुए शुरुआती समय में ही शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए। बाग व गंधवानी की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर संबंधित बीएमओ पर नाराजगी व्यक्त कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के उपचार एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। इस संबंध में शतप्रतिशत मैनेजमेंट किए जाने के निर्देश दिए गए।

शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की समीक्षा में नियमित टीकाकरण, गुह आधारित नवजात शिशु देखभाल (IBBT), IBBT टीकाकरण तथा



व्हाट्सएप-1, स्कू 2 एवं व्हाट्सएप की उपलब्धियों में वृद्धि हेतु माइक्रोप्लान बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनसीडी कार्यक्रम अंतर्गत हाईपरटेंशन एवं डायबिटीज मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार तथा कंट्रोल रेट में वृद्धि लाने हेतु नियमित फॉलोअप एवं दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसी के साथ ही जिला चिकित्सालय एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में रेबीज वैक्सीन तथा स्नेक बाइट एंटी-वेनम वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा आवश्यकता अनुसार त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राहत योजना, हज़रत गुणवत्ता प्रमाणीकरण, सिक्ल सेल जांच तथा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम

को भी समीक्षा की गई। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, चिन्हित संस्थाओं का प्रमाणीकरण पूर्ण करने तथा लक्ष्यनुसार जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री मीना ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य के विभिन्न पैरामीटर पर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुष अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला नोडल अधिकारी, समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, बीसीएम, बीपीएम एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



गौशाला विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है तथा सभी अधिकारियों और संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ कार्यों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि गौशाला पूर्ण होने के बाद यहां लगभग 10 हजार

गौमाताओं के निवास और देखभाल की व्यवस्था की जा सकेगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि यह परियोजना केवल गौसेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से भी जोड़ा गया

है। मुख्यमंत्री डॉ यादव के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत परिसर में तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही आसपास के नालों की सफाई, बोरी बंधान एवं चेक डैम निर्माण जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो सके। उन्होंने बताया कि गौशाला परिसर में नक्षत्र वाटिका का भी विकास किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र गौसंवर्धन, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का एक आदर्श केंद्र बनेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर गौशाला को गौमाताओं के उपयोग हेतु समर्पित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने समीप के ग्राम बड़गोन्दान में प्राचीन काल की बावड़ी का अवलोकन भी किया। इस बावड़ी का जीर्णोद्धार भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कराया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

राजगढ़ जिले में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं उपार्जन

● कलेक्टर डॉ. मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में रचा नया कीर्तिमान

राजगढ़, निप्र। राजगढ़ जिले में वर्ष 2026-27 के दौरान गेहूं उपार्जन में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन, सतत मॉनिटरिंग एवं प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदी संपन्न हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादितसे प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 108 गेहूं उपार्जन केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष 72 हजार 565 किसानों से समर्थन मूल्य पर कुल 44 लाख 55 हजार 784 क्विंटल एफएक्यू (गुणवत्ता पूर्ण) गेहूं का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूं का कुल मूल्य लगभग 1169.64 करोड़ रुपए रहा। साथ हीगत वर्ष 2025-26 में जिले में 52 हजार 176 किसानों से 38 लाख 23 हजार 862 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया था, जिसकी राशि 994.20 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार वर्ष 2026-27 में जिले में गत वर्ष की तुलना में 20 हजार 389 अधिक किसानों ने उपार्जन केंद्रों पर गेहूं विक्रय किया तथा 6 लाख 31 हजार 922 क्विंटल अधिक गेहूं की खरीदी की गई। कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा पूरे उपार्जन कार्य की नियमित समीक्षा की गई तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। परिणामस्वरूप जिले में उपार्जन कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले में हुई रिकॉर्ड गेहूं खरीदी को किसानों के विश्वास, प्रशासन की सतत निगरानी तथा समन्वित कार्यप्रणाली का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है।

श्रमोदय मॉडल आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ

● विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित

राजगढ़, निप्र। श्रमोदय मॉडल आईटीआई, भोपाल में नवीन सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को रोजगारपरक एवं उद्योग आधारित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। संस्थान की ओर से विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें जांब गाटी एवं प्लेसमेंट सहायता, निःशुल्क छात्रावास सुविधा, निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा निःशुल्क अध्ययन सामग्री शामिल हैं। प्रशिक्षण अधिकारी श्रमोदय मॉडल आईटीआई द्वारा बताया गया कि प्रवेश केवल मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत द्विप्राधियों के बालक एवं बालिका को दिया जाएगा। आईटीआई की विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश लेकर विद्यार्थी अपने उच्चल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। प्रवेश, ट्रेड, पात्रता एवं अन्य जानकारी के संबंध में संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा 3 एवं 4 जून, 2026 को जीरापुर एवं नरसिंहगढ़ में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन 31 मई को

राजगढ़, निप्र। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले के निर्देशन में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन 31 मई, 2026 को किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं एवं बच्चों को तम्बाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, टी.बी., हृदय रोग आदि से बचाव करने के लिये जन जागरूकता लाना है। वर्ष 2026 के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2026 (31 मई) की थीम आकर्षण का पर्दाफाश-निकोटीन और तम्बाकू की लत का पर आधारित है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। जिनमें जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित तम्बाकू नियंत्रण केन्द्र द्वारा तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली गम्भीर बीमारियों पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

बाल श्रम के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने दिए जागरूकता, निरीक्षण एवं पुनर्वास के निर्देश, निर्माण एजेंसियों एवं विभागों को श्रमिकों का डेटा संकलित करने के निर्देश



राजगढ़, निप्र। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल श्रम उन्मूलन, पुनर्वास, जनजागरूकता एवं कानून के पालन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ.

मिश्रा ने निर्देश दिए कि जिले में बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमित निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसाय में कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीआईयू, पीडब्ल्यूडी, आईएस सहित



सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि उनके अंतर्गत कार्यरत असंगठित श्रमिकों का संपूर्ण डेटा तैयार किया जाए। साथ ही ई-श्रम पोर्टल पर जिन श्रमिकों का पंजीयन नहीं हुआ है, उनकी प्रविष्टि संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी लेकर सुनिश्चित करें।

जनपद स्तर पर चलेंगे जागरूकता अभियान

बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि आगामी एक माह के भीतर जनपद स्तर पर बैठकें आयोजित कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। श्रम कानूनों में वर्ष 2020 में हुए बदलावों की जानकारी आमजन एवं श्रमिकों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की

1098 हेल्पलाइन शिकायतों की होगी नियमित समीक्षा

बैठक में बाल श्रम कानून के दंडात्मक प्रावधानों, पुनर्वास व्यवस्था एवं जिला टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएं तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर डॉ. ज्योदति बाबैया, एसडीओपी राजगढ़, श्रम अधिकारी श्री सौरभ कुमार गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री श्यामबाबू खरे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने तथा श्रम में सलिस बच्चों के पुनर्वास के लिए समन्वित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही बाल श्रम से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई, लगाए गए जुर्माने एवं पुनर्वास की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

खाद वितरण में किसानों को कोई परेशानी न हो, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर डॉ. मिश्रा

ई-टोकन प्रणाली से ही किसानों को खाद वितरण सुनिश्चित करने दिए निर्देश

कृषि एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित

राजगढ़, निप्र। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में किसानों को खाद वितरण व्यवस्था की बर्तमान समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि किसानों को खाद का वितरण केवल ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित रहे।

उन्होंने सभी अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन ई-टोकन प्रणाली पोर्टल का अवलोकन करें तथा पोर्टल पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रहे, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने डीएम सीसीबी ब्यावरा-सुवालिया, माचलपुर एवं



सारंगपुर द्वारा ई-टोकन प्रणाली से खाद वितरण नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पंचायत समितियों की जांच के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए गए। बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी संस्था प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि खाद

वितरण के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही।

पेयजल स्रोतों का निरीक्षण एवं रिचार्ज संरचनाओं पर प्रशिक्षण आयोजित

राजगढ़, निप्र। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत पेयजल संकट निवारण के उद्देश्य से नरसिंहगढ़ विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में पेयजल स्रोतों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकांश ग्रामों में नलकूप आधारित जल स्रोतों के सूखने एवं जल स्तर में गिरावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त समस्याओं के निराकरण हेतु सोर्सिस्टेनेबिलिटी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों में रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज शाफ्ट जैसी भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों एवं संबंधित मैदानी

अमल को रिचार्ज शाफ्ट संरचना निर्माण एवं उसके तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके। अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में क्षेत्र के हैंडपंपों का भी सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण के माध्यम से अनुपयोगी, बंद एवं कम जल उपलब्धता वाले हैंडपंपों की पहचान कर उनके सुधार एवं पुनर्भरण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से भी जल संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने तथा वर्षा जल संचयन एवं जल स्रोतों के संरक्षण हेतु सहयोग करने की अपील की गई है।

किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करें: कलेक्टर डॉ. मिश्रा



राजगढ़, निप्र। जिला उपार्जन समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपार्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों का भुगतान किसी कारणवश फेल हुआ है, उनके खातों की तत्काल ई-केवाईसी कराई जाए अथवा

आवश्यकता अनुसार खाता परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में कहा कि उपार्जन कार्य शासन की प्राथमिकता से जुड़ा विषय है, इसलिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करें।

जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित



उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन खरीदी केंद्रों पर गेहूं का परिवहन अभी शेष है, वहां से शीघ्र परिवहन कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि उपार्जित गेहूं का समय पर भंडारण सुनिश्चित हो सके।

बैठक में उपार्जन कार्यों की प्रगति, भुगतान की स्थिति एवं परिवहन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला उपार्जन समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



एनएसएस एवं युवा रेडक्रास द्वारा विद्यार्थियों ने लिया जल संरक्षण का संकल्प

राजगढ़, निप्र। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में 'जल गंगा संवर्धन-अभियान' के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं युवा रेडक्रास इकाई के संयुक्त तत्वाधान में प्रेरणादायक एवं जागरूकता से परिपूर्ण शपथ कार्यक्रम एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा तथा आने वाली पीढ़ियों के उच्चल भविष्य हेतु जल बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था प्रभारी प्राचार्य डॉ. मंगलेश सोलंकी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शैलेंद्र कुमार मेवाड़ा ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए कहा कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यदि आज जल संरक्षण के प्रति गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में जल संकट मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. मंगलेश सोलंकी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा शक्ति में सुधार के साथ-साथ पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

पंचायत भ्याना में प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बावड़ी जीर्णोद्धार के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं जीर्ण-क्षीण सीढ़ीदार कुओं की साफ-सफाई, संरचनात्मक मरम्मत एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। बावड़ी में जमा कचरे एवं गाद को हटाकर उसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार के साथ-साथ पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

रिचार्ज संरचनाओं से भू-जल संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल



राजगढ़, निप्र। जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विभिन्न रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत निपानियातुला में रिचार्ज संरचना

गतिविधि अंतर्गत कंटर ट्रैक निर्माण का कार्य कराया गया। कंटर ट्रैक पहाड़ी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को रोकने तथा मिट्टी के कटाव को कम करने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली खतियां (नोलियां) होती हैं। इन्हें समान ऊंचाई वाले बिंदुओं के समतल खोदा

जाता है, जिससे वर्षा का पानी सीधे बहने के बजाय इन खतियों में एकत्र होकर धीरे-धीरे भूमि के भीतर रिस सके। ग्राम पंचायत निपानियातुला में कुल 69 कंटर ट्रैक के अंतर्गत 1794 गड्डे/खतियां निर्मित की गई हैं। प्रत्येक गड्डे से लगभग 100 लीटर पानी

भूमि के भीतर समाहित होने का अनुमान है। इस प्रकार एक वर्षाकाल में लगभग 179 घनमीटर जल भू-गर्भ में पहुंचाकर भू-जल स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य जल संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण से संतुलन एवं कृषि के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भैसवामाता में कंटर ट्रैक निर्माण कार्य किया गया, जिससे वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। वहीं ग्राम